तक बढ़ाने का काम इस वित्तीय विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस बजट के जो प्रस्ताव हैं, वे अमीरों और उच्च आय अर्जित करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

जहां तक फ्रिंज बेनफिट टैक्स, एफबीटी को हटाने का प्रस्ताव है, इससे औद्योगिक संस्थानों को सीधे लाभ पहुंचेगा, क्योंकि अब उन्हें कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न फायदों पर कर नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये कम्पनियां इसका लाभ अपने कर्मचारियों को देंगी या नहीं देंगी, इसको वित्त मंत्री जी को देखना है।

वित्त मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। लोग उपहार लेकर काले धन को सफेद करने का काम करते थे। अब इस बजट में अगर 50 हजार रुपए से ज्यादा के नकद के उपहार मिलते हैं, तो आप को कर चुकाना होगा। जो 50 हजार रुपये तक के उपहार होते थे, लोग इसको गहनों के रूप में, अन्य सामान के रूप में ले लिया करते थे, जिससे काले धन को सफेद करने का काम होता था, लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री जी ने यह प्रॉविजन किया है कि यह बजट के दायरे में आएगा।

सर, यह जो सरल फार्म है, इसको जब लोग भरना सीख लेते हैं, तो बड़ी विडम्बना है कि इसको बदल दिया जाता है। इस समय जो आईटीआर फार्म है, वह ठीक है। लेकिन इसको हर साल बदल देने का काम होता है। सरकार जी.एस.टी. कानून को बनाने जा रही है। वित्त मंत्री जी ने 1 अप्रैल, 2010 से गुड्स सर्विस टैक्स लागू करने की बात कही है, ...लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको अप्रैल, 2010 से लागू करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा है, उसको तय करना होगा। इस प्रकरण पर अभी केंद्र और राज्यों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि यह सिंगल रेट होगा या मल्टीपल रेट होगा, इस पर भी बात नहीं हो पाई है। राज्यों में केंद्रीय उत्पाद कर और वैट की जो प्रणाली है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। अप्रैल 2010 से पहले इस पर बात पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी - हालांकि अच्छी बात है कि इसको लागू किया जाए, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन हमें संशय लगता है कि यह अप्रैल 2010 तक पूरा हो भी पाएगा। सबसे बड़ी चिंता की जो बात है, वह राजकोषीय घाटा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर सभी अनुमानों को लांघता हुआ सकल घरेलू उत्पाद का करीब 8.9 प्रतिशत हो जाएगा। यदि इस घाटे में राज्य सरकारें और बजट से हटकर बजटेतर राशियां शामिल हो जाएं तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत हो जाएगा। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट, किसानों की जो 65,000 करोड़ रुपए ऋण की माफी हुई है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार, उत्पादन और सीमा शुल्कों में जो कमी की गई है और सामाजिक क्षेत्र की अन्य योजनाओं की घोषणाओं के कारण ऐसी आशा है कि 2009-10 तक सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। यह सकल घरेलू उत्पाद का 9-10 प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे में राजकोषीय घाटे को सुधारने के लिए ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : यादव जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री नन्द किशोर यादव : उपसभाध्यक्ष जी, एक मिनट।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मैं क्या करूं?

श्री नन्द किशोर यादव : सर, बैकबेंचर्स को आपका संरक्षण चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : संरक्षण हमेशा है, लेकिन एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री नन्द किशोर यादव : सर, इस देश में जो तमाम तरह की निधियां हैं, करीब 110 लाख करोड़ के आसपास हैं, ये निधियां हैं, इनमें सड़क विकास निधि, रेलवे सुरक्षा निधि, रक्षा निधि, पेंशन निधि, कर्मचारी कल्याण निधि इत्यादि है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन निधियों को देश की मुख्यधारा में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे में सुधार होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बता देना चाहूंगा कि मुझे अर्थशास्त्र और फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लंबे अरसे से एक पोलिटिकल वर्कर और सोशल वर्कर के रूप में समाज के बीच में काम करने का जो मौका मिला है, उसके आधार पर ही देश की जो आर्थिक नीति है, जिसकी झलक इस बजट में मिलती है, उसको देखता हूं। अभी हमारे मित्र रवि शंकर प्रसाद जीने कहा कि प्रणब बाबू जो बजट पेश कर रहे हैं देश बहुत उत्सुकता के साथ उसको देख रहा है। मैं इस मामले में उनके साथ सहमत नहीं हूं। इस देश के आम आदमी को बजट से क्या मतलब है? देश की आर्थिक स्थिति, देश की आजादी के बाद लगातार जो बजट पेश किए जाते रहे हैं, उनसे इस देश के आम आदमी की हालत सुधरी नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं कि उसकी हालत बिगड़ी है। उसे लगता है कि आजादी के इतने बरस बाद हमें अब ठहरकर देखना चाहिए कि आजादी के बाद जिन आर्थिक नीतियों को हम चलाते रहे, उन नीतियों की वजह से देश में गरीबी घटी है, देश में बेरोजगारी घटी है, देश में भ्रष्टाचार घटा है, यह जांचने, परखने का समय आ गया है। मैं यह मानता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ इस देश में जो जंग हुई थी और हमारी आजादी के नायकों ने देश के लोगों के साथ जो वायदा किया था, उसकी वायदाखिलाफी हुई है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मानिएगा कि हमारी आजादी के संघर्ष के मुख्य नायक महात्मा गांधी थे। उन्होंने ही आजादी के बाद देश की तस्वीर क्या होगी, आजादी के बाद देश की आर्थिक नीति क्या होगी, इसके बारे में जनता को शिक्षित करने और बताने का काम किया था। आजादी के बाद देश की आर्थिक नीति क्या होगी, इस संबंध में मैं गांधी जी के शब्दों को कोट करके आपके सामने रखना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जिस तरह सच्चे नीति धर्म में और अच्छे अर्थ शास्त्र में कोई विरोध नहीं होता...। "...जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और बलवानों को निर्बलों का शोषण करके धन का संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता है।" यह महात्मा गांधी ने कहा है। आगे उनका कहना है, "आर्थिक समानता के लिए वह तो एक झूठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अपना कर हम मृत्यु को न्यौता देंगे। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता है, वह समान भाव से सबकी भलाई का, जिनमें कमजोर भी शामिल हैं, प्रयत्न करता है।" यह गांधी जी का कहना है। आज तक हमारे देश में जो आर्थिक नीति चली है, अगर इस कसौटी पर हम उसे जांचने और परखने का काम करेंगे, तो पता चलेगा कि हम देश में जो आर्थिक नीति चला रहे हैं, वह नैतिक नहीं, अनैतिक है। इसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इस देश में एक से बढ़ कर एक स्कैंडल्स हो रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी परसों-नरसों यहां Information and Technology Ministry के बारे में चर्चा हो रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजीशन सहित कई लोगों ने संदेह जताया, मंत्री से pointed सवाल किया कि इसमें 60-70 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। मैं भी यहां बैठा सुन रहा था और मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। आज के अखबारों में भी खबर छपी है, जिसमें बताया गया है कि कारपोरेट सेक्टर में लड़ाई हो रही है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सरकार 50 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा देने जा रही है। यही आर्थिक नीति इस देश में चल रही है।